

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 11 अप्रैल 2026 वर्ष-9, अंक-76 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com  www.facebook.com/krantisamay1  www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा

दिल्ली वाले घर से मिले थे जले हुए नोट

प्रयागराज (एजेसी)। कैश कांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि उनके दिल्ली वाले आवास पर जले हुए नोट मिले थे। इस विवाद के बाद उनका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद तबादला कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल, 2025 को शपथ ली थी। फिलहाल उनके खिलाफ आरोपों के संबंध में एक आंतरिक जांच चल रही है। इस मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम



बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति आगामी मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। पिछले साल 12 अगस्त को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग वाला एक बहुदलीय नोटिस स्वीकार करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा की ओर से दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति गठित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। यह निर्णय न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया था। 21 जुलाई, 2025 को संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की बात चली थी।

आपको प्रणाम कर रहे हैं पहले तो हम यहीं ना थे

पुरानी संसद देख भावुक हुए बिहार सीएम नीतिश कुमार

पटना (एजेसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने शुक्रवार को संसद भवन में राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली। वे पुराना संसद भवन देखकर भावुक हो गए। वे नए संसद भवन से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनकी नजर सामने स्थित पुराने संसद भवन पर पड़ी तो वे उसे कुछ पल निहारते रहे। इसके बाद उन्होंने पुराने भवन की ओर हाथ उठाकर हिलाया और फिर हाथ जोड़ लिए। नीतिश कुमार 21 साल बाद संसद भवन में लौटे हैं। उन्होंने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली और विधिवत संसद बन गए। शपथ लेने के बाद वे अपने



सुरक्षा कर्मियों और अन्य कुछ लोगों के साथ नए संसद भवन से बाहर आए। बाहर आने पर उनकी नजर जैसे ही पुराने संसद भवन पर पड़ी तो वे कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ उठाया और संसद भवन की ओर से ऐसे हिलाया जैसे किसी व्यक्ति से कुछ कहना चाह रहे हों। पुराने संसद भवन को निहारते हुए भावनाओं में डूबे नीतिश कुमार ने उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर अभिवादन की मुद्रा में हाथ भी जोड़े। उन्होंने पुराने संसद भवन को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा- आपको प्रणाम कर रहे हैं। पहले तो हम यहीं ना थे। पुराने संसद भवन को देखकर नीतिश कुमार की स्मृतियां ताजा हो गईं।

कठिन राह और हौसलों की

साइकिल पर भारत यात्रा

● 5700 किमी की दूरी तय कर कोलकाता पहुंची आशा ● एनसीसी कैडेटों ने किया स्वागत



कोलकाता (एजेसी)। हजारों किलोमीटर की कठिन राह, बदलते मौसम, अनगिनत चुनौतियां- लेकिन भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में हौसले बुलंद हों तो हर मजिल करीब लगती है। इसी जज्बे की जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी हैं आशा मालवीय, जिन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के जरिए नारी शक्ति, देशभक्ति और अदम्य साहस का

एसा संदेश दिया है, जिसने युवाओं के दिलों में नई ऊर्जा भर दी है। 78वें भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट, पर्वतारोही व साइकिलिस्ट आशा मालवीय ने 11 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर से 7,800 किलोमीटर लंबी देशव्यापी पूर्व-पश्चिम एकल साइकिल अभियान (यात्रा) की शुरुआत की थीं। इस सफर में वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को पार करते हुए करीब 5,700 किलोमीटर की दूरी तय कर कोलकाता पहुंचीं, जहां गुरुवार को एनसीसी कैडेटों व अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 7,800 किलोमीटर में से अब तक वह लगभग 5,700 किमी की दूरी तय कर चुकी हैं, जबकि उनका अंतिम लक्ष्य चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र किबितु तक पहुंचना है। इस प्रेरणादायक अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, देशभक्ति और अटूट साहस का संदेश देना है। कोलकाता में एनसीसी के बंगाल व सिक्किम निदेशालय में गुरुवार को उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों को उनसे सीधे संवाद का अवसर मिला।

बैलगाड़ियां और ढोल लेकर फिर सड़क पर उतरे किसान

● नए खरीद नियमों पर मड़के अन्नदाता, आंदोलन शुरू



चंडीगढ़ (एजेसी)। हरियाणा के किसानों ने गेहूं खरीद के नए नियमों का खल्ल कर विरोध किया है। बैलगाड़ी, ढोल-नागाड़ी और नारों के साथ उन्होंने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। नए नियमों में बायोमेट्रिक सत्यापन, वाहन ट्रैकिंग, जियोफेंसिंग और तीन स्तर की जांच शामिल

है। किसान इन्हें बोलिबल और अपमानजनक बता रहे हैं। यमुनानगर की सदहूरा मंडी और जिंद की जुलाना मंडी में किसानों ने पुरानी ट्रॉली और बैलगाड़ी से फसल लाकर सरकार के डिजिटल सिस्टम का विरोध जताया। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को चार घंटे हाईवे ब्लाक करने की घोषणा की है। नए खरीद नियमों के तहत किसानों को पहले मेरी फसल-मेरा ब्यूरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता है। मंडी पहुंचने पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, ट्रैक्टर-ट्रॉली की फोटो, वाहन नंबर और जियोफेंसिंग के जरिए फसल की पुष्टि करनी होती है। सरकार का दावा है कि इससे पड़ोसी राज्यों से सस्ते चावल की घुसपैट रोकी जा सकेगी।

स्वदेशी मिसाइलों से लैस होंगे राफेल विमान

रक्षा मंत्रालय ने बनाया प्लान, खरीदो और बनाओ की नीति तैयार

नई दिल्ली (एजेसी)। भारत जिन 114 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्लान बना रहा है, उनको लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों और हथियार प्रणालियों को इनमें एकीकृत किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि खरीदो और बनाओ सौदे के तहत होने वाली सरकार-से सरकार डील में तथाकथित इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट को अनिवार्य किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय से उम्मीद है कि वह अगले महीने फ्रांसीसी जेट निर्माता कंपनी डसॉल्ट को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगा और उसके बाद अनुबंध पर बातचीत शुरू होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 फरवरी को इस सौदे को मंजूरी दे दी थी।



96 फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे

मामले के जानकार लोगों ने कहा कि योजना यह है कि 3.25 लाख करोड़ रुपये की इस मेगा डील के फाइनेल कॉन्ट्रैक्ट में आईसीडी को पक्का कर दिया जाए। आईसीडी एक बहुत ही जरूरी सिस्टम इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट है, जो किसी सिस्टम और उसके सब-सिस्टम के बीच के सभी अहम प्रोटोकॉल को कंट्रोल और डिफाइन करता है। डीएसी द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, 18 फाइटर जेट फ्रांस से पलाई-अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी 96 भारत में ही बनाए जाएंगे, जिनमें 25 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। इस तरह की रिपोर्टों के बीच कि इस मेगा डील में एक रुकावट आ गई है, क्योंकि फ्रांसीसी राफेल निर्माता डसॉल्ट ने भारत को लड़ाकू विमान का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कोई भी देश ये मालिकाना सॉफ्टवेयर कोड (जो रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हथियार एकीकरण को नियंत्रित करते हैं) किसी तीसरे देश को नहीं देता है और यह डील पूरी तरह से सही रास्ते पर है। ये सोर्स कोड असल में पूरे लड़ाकू विमान को नियंत्रित करते हैं, जिसमें एवियोनिक्स, टारगेट ट्रैकिंग, पलाइंट कंट्रोल, हथियार लॉन्च और हथियार छोड़ने के एल्गोरिदम शामिल हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि यह कोड मूल उपकरण निर्माता की बौद्धिक संपदा है, जिसे सबसे करीबी सहयोगियों के साथ भी साझा नहीं किया जाता है।



भारत तेजस पर दे रहा ध्यान

भले ही भारत ने अमेरिका या रूस, किसी से भी पांचवीं पीढ़ी के विमान खरीदने का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन वह भविष्य के लिए स्वदेशी रूप से तेजस मार्क एलए के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही, वह लंबी दूरी की मिसाइलों और दो इंजन वाले एलए पर भी काम कर रहा है, ताकि विदेशी हवाई जेटफॉर्म, बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर अपनी निर्भरता कम कर सके।

बंगाल में महिलाओं को 3000 का वादा

● गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र ● घुसपैट पर जीरो टॉलरेंस नीति, 7वें वेतन आयोग का वादा

नई दिल्ली (एजेसी)। बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक 13 दिन पहले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने चुनावी वादों का पिटाया खोल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र को पार्टी ने भरोसा पत्र नाम दिया गया है। इसमें महिलाओं से लेकर युवाओं तक, प्रमुख वोट वर्ग के लिए नकदी के वादे किए



गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया।

घुसपैट को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति करेंगे लागू

अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार घुसपैट को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। हम घुसपैटियों को बाहर निकाल देंगे और बंगाल को सुरक्षित बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बकाया डीए भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और सरकार बनने के 45 दिन के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।

बंगाल की महिलाओं के लिए किए बड़े वादे

संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएँ की गई हैं। इसके तहत केजी से पीजी तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करने और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। साथ ही हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपये देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा घोषणापत्र में टीएमसी सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी करने का वादा, सातवें वेतन आयोग को लागू करने, घुसपैट और गौतस्करों पर रोक लगाने का संकल्प, उत्तर बंगाल में प्रौद्योगिकी का संस्थान खोलने का संकल्प है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र भरोसे का है।

डॉक्टर हरिवंश फिर से बने राज्यसभा सांसद

● जेडीयू ने नहीं भेजा तो सरकार ने किया नामित

नई दिल्ली (एजेसी)। राज्यसभा के उपसभापति रहे हरिवंश को फिर से राज्यसभा की सदस्यता मिल गई है। इस बार उन्हें जेडीयू ने राज्यसभा नहीं भेजा था। माना जा रहा था कि अब राज्यसभा का उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन उन्हें एक और चांस मिल गया है। यह मौका उन्हें नामित करके दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आर.एस.जे.आर. के चलते उन्हें मनीनीत किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि एक मनीनीत सांसद के रिटायरमेंट से जो रिक्ति हुई है, उस स्थान पर हरिवंश को मौका दिया गया है।



करीबी माना जाता था, लेकिन बीते कुछ समय से उनके रिश्तों में वह गर्मजोशी नहीं दिखी है। इसी वजह से मौका नहीं दिया।

अंतरिक्ष में इतिहास रचने के करीब भारत!

● गगनयान के दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट में इसरो को शानदार कामयाबी

नई दिल्ली (एजेसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। गगनयान मिशन का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यात्रियों को

अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना है। जब अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके वापस वापसी के दौरान पैराशूट सिस्टम की भूमिका अहम होगी। मॉड्यूल की गति को धीमा करने लौटेंगे, तो उनका कू मॉड्यूल (वह कैस्पूल जिसमें वे बैठे होंगे) तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। इस और उसे सुरक्षित रूप से समुद्र (या सतह) पर उतारने के लिए एक बेहद जटिल पैराशूट प्रणाली का इस्तेमाल होता है।



जल्द इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि यह सफलता गगनयान मिशन की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। किसी भी मानव मिशन में इंसानी जान की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। यह परीक्षण सुनिश्चित करता है कि लैंडिंग के वक्त कोई दुर्घटना नहीं होगी। ऐसे हर सफल परीक्षण के साथ इसरो गगनयान के फाइनेल लॉन्च के एक कदम और करीब पहुंच जाता है। गगनयान भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 दिन के मिशन के लिए भेजा जाएगा।

● गलत ट्रॉजेक्शन कैलिकुल करने का मौका मिलेगा, आ गया नया प्रस्ताव

10 हजार से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर अब 1 घंटे का रहेगा होल्ड

● आरबीआई ने 'किल स्विच' का सुझाव भी दिया, डिजिटल फ्राड रुकेगा

मुंबई (एजेसी)। जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपको 10 हजार से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रॉजेक्शन तुरंत न हो। उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। इससे शाहकों को गलत ट्रॉजेक्शन रोकने या कैसिल करने का मौका मिलेगा। देश में बढ़ते डिजिटल फ्राड को रोकने के लिए आरबीआई ने ये प्रस्ताव रखा है। आरबीआई का मानना है कि जालसाज अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर जल्दबाजी में पैसे ट्रॉसफर करवाते हैं, यह देरी उस दबाव को खत्म करेगी। फिलहाल ज्यादातर डिजिटल ट्रॉजेक्शन तुरंत होते हैं, जिससे यूजर को सोचने या गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता।



सोनिबर सिटीजंस के लिए 'ट्रस्टेड पर्सन' सुविधा- 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा और सख्त होगी। 50,000 रूपये से ज्यादा के ट्रॉजेक्शन के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन (भरोसेमंद व्यक्ति) की मंजूरी जरूरी हो सकती है। यह फ्राड के खिलाफ सुरक्षा की एक दूसरी लेयर की तरह काम करेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या मर्चेन्ट को पैसे भेज रहे हैं, जिसे आप जानते हैं, तो आप उसे व्हाइटलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए 'किल स्विच'

आरबीआई ने एक किल स्विच का सुझाव भी दिया है। अगर किसी शाहक को लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है या कोई गलत ट्रॉजेक्शन हो रहा है, तो वह एक किल स्विच से अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा। पिछले साल देश में डिजिटल फ्राड के कारण होने वाला नुकसान 22 हजार करोड़ रूपये के पार पहुंच गया। आरबीआई के अनुसार 10 हजार रूपये से ऊपर के ट्रॉजेक्शन कुल फ्राड केस का सिर्फ 45 फीसदी हैं, लेकिन कुल फ्राड वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी 98.5 फीसदी है। इसी को ध्यान में रखते हुए 10 हजार की लिमिट तय की गई है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

संसेक्स 918, निफ्टी 275 अंक ऊपर आया

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी होने से बाजार में ये तेजी आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई संसेक्स 918.60 अंक बढ़कर 77,550.25 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 275.50 अंक उछलकर 1.10 24,050.60 पर बंद हुआ। बाजार में बढ़त ऑटो स्टॉक्स में

तेजी से आई है। इस कारण निफ्टी ऑटो में सबसे अधिक 2.85 फीसदी की तेजी रही जबकि निफ्टी रियल्टी में 2.08 फीसदी और निफ्टी फार्माशियल सर्विसेज में 2.06 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 2.01 फीसदी, निफ्टी की तेजी के साथ बंद हुआ। सूचकांकों में केवल निफ्टी आईटी ही 1.91 फीसदी गिरावट पर बंद हुआ। आज लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी उछल आया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 865.20 अंक बढ़कर 57,843.95 और निफ्टी



बेफिक्र नहीं हैं और सतकता के साथ निवेश कर रहे हैं।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 35 पैसे की गिरावट के साथ ही 92.85 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया 10 पैसे की तेज होकर 92.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा

विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.51 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 98.69



पर रहा।

एडीबी ने भारत की विकास दर 6.9 फीसदी रहने का अनुमान लगाया

घरेलू मांग और आसान वित्तीय परिस्थितियों से वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद



नई दिल्ली।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। बैंक के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और आसान वित्तपोषण परिस्थितियों अर्थव्यवस्था को सहारा देंगी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के कम शुल्क और निवेश माहौल में सुधार से भी वृद्धि को समर्थन मिलेगा। वहीं 2027-28 में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.3 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पश्चिम एशिया में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने से

भारत एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा अपनाए, बढ़ेगी दक्षता और घटेगा लाभों का दोहराव एडीबी

पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और दिव्यांगता लाभों को जोड़ने से बेहतर लक्ष्यीकरण और कम होगा राजकोषीय बोझ

नई दिल्ली।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को सलाह दी है कि वह अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा अपनाए। इससे न केवल योजनाओं में दोहराव कम होगा, बल्कि लाभार्थियों तक सहायता बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी और सरकारी खर्च अधिक संतुलित होगा। एडीबी ने अपनी एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बैंक ने कहा है कि भारत को एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा अपनाना चाहिए, जिससे विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय बढ़े और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं समान लाभार्थी समूहों को कवर करती हैं, लेकिन इनके बीच समन्वय सीमित है। इसके कारण कई बार एक ही व्यक्ति या परिवार को अलग-अलग योजनाओं से समान प्रकार के लाभ मिल जाते हैं, जिसे 'लाभों का दोहराव' कहा जाता है। एडीबी ने सुझाव दिया कि पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और दिव्यांगता कवरेज जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक साझा ढांचे में जोड़ा जाए। इसमें अंशदायी योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे लाभ वितरण अधिक व्यवस्थित और लक्षित हो सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें राज्यों की जनसंख्या संरचना, रोजगार पैटर्न और वित्तीय क्षमता के अनुसार अलग-अलग होती हैं।



इसलिए एकीकृत ढांचा राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन देगा। मनीला स्थित इस बहुपक्षीय संस्था ने यह भी बताया कि इस सुधार से सरकारें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सुरक्षा भूमिका को बनाए रखते हुए राजकोषीय लागत को नियंत्रित कर सकेंगी। इससे बचने वाले संसाधनों को बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी जैसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। एडीबी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

आरबी आई डिजिटल भुगतान में सुरक्षा बढ़ाने जाए नियम लागू करेगी

बड़े लेनदेन में देरी से क्रेडिट, डिजिटल भुगतान को बंद करने का विकल्प

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई नए और सख्त सुरक्षा उपग्रहों का प्रस्ताव रखा है। इनमें बड़े लेनदेन में देरी से क्रेडिट, डिजिटल भुगतान को बंद करने का विकल्प और कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है। केंद्रीय बैंक ने इस पर सुझाव और प्रतिक्रिया 8 मई तक मांगी है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में तेजी से बढ़ रही धोखाधड़ी पर चिंता जताते हुए एक क्विक चर्चा पत्र जारी किया है। इसमें



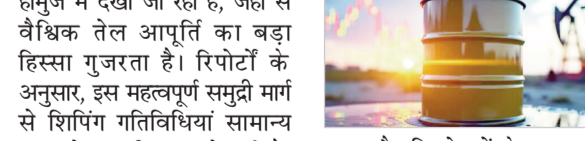
पड़ने पर उचित प्रमाणीकरण के बाद ही इन्हें दोबारा चालू किया जा सकेगा। बैंक ने खाताधारकों को यह सुविधा देने का भी सुझाव दिया है कि वे अपने खाते में विभिन्न प्रकार के डिजिटल लेनदेन की सीमाएं तय कर सकें। साथ ही, सख्त गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ खातों में क्रेडिट सीमा लगाने का भी प्रस्ताव है, ताकि मूल अकाउंट जैसी धोखाधड़ी पर रोक लग सके। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का भी प्रावधान सुझाया गया है। इनके बड़े डिजिटल लेनदेन के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त

आपूर्ति संकट और मध्य पूर्व तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

होमजुंज जलडमरूमध्य में बाधा और अमेरिका-ईरान तनाव से ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में बढ़त

मुंबई।

वैश्विक कच्चे तेल बाजार में शुक्रवार को फिर तेजी देखने को मिली, जब भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति बाधाओं की आशंकाओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका-ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता, मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों पर जोखिम के कारण तेल की कीमतों में उछल दर्ज किया गया। ब्रेंट क्रूड 1.13 प्रतिशत बढ़कर 97.01 डॉलर प्रति बैरेल पर पहुंच गया, जबकि वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.39



होमजुंज में देखा जा रहा है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिपोर्टों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से शिपिंग गतिविधियां सामान्य स्तर से काफी कम हो गई हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई पर दबाव बना है। मध्य पूर्व में इजरायल और लेबनान के बीच जारी तनाव ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है। वहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि सीजफायर की शर्तों का पालन नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने इसे कम संभावना वाला

इकॉनोमिक्स फंड में मार्च में निवेश 56 फीसदी बढ़कर 40,450 करोड़

गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटकर 2,266 करोड़ रुपये रह गया

नई दिल्ली।

मार्च महीने में बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा शेयर आधारित म्यूचुअल फंडों में बना रहा। इकॉनोमिक्स फंड में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि डेट फंडों से भारी निकासी ने कुल उद्योग आंकड़ों को प्रभावित किया। मार्च महीने में भारतीय शेयर आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहा, जिससे शुद्ध निवेश 56 प्रतिशत बढ़कर 40,450 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। फरवरी में यह आंकड़ा 25,978 करोड़ रुपये था। बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद इकॉनोमिक्स फंडों में लगातार निवेश बढ़ा, जिसका मुख्य कारण प्लेक्सि कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों में भारी प्रवाह रहा। प्लेक्सि कैप फंड में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश दर्ज किया गया, जबकि स्मॉल कैप में 6,263 करोड़ रुपये और मिड कैप में 6,063 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। व्यवस्थित निवेश योजना यानी एसआईपी के माध्यम से भी निवेश बढ़कर 32,087 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले महीने से अधिक है। हालांकि इंग्लैसएसएस श्रेणी में मामूली निकासी देखी गई। वहीं गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटकर 2,266 करोड़ रुपये रह गया। दूसरी ओर डेट फंडों से भारी निकासी के कारण पूरे उद्योग में कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी दर्ज हुई, जिससे एयूएम घटकर 73.73 लाख करोड़ रुपये रह गया। यह प्रवृत्ति निवेश धारणा में बदलाव को दर्शाती है।

रियल एस्टेट दिवाला मामलों में परियोजना पूर्णता को प्राथमिकता देने की सिफारिश

आईबीबीआई की विशेष समिति ने 155 सुझाव दिए, घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर



नई दिल्ली।

रियल एस्टेट क्षेत्र के दिवाला मामलों के समाधान में अब वित्तीय वसूली की बजाय अटकती परियोजनाओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। रियल एस्टेट से जुड़े दिवाला मामलों में घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए परियोजना-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है। भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा गठित एक विशेष समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे मामलों में पूरी कंपनी को दिवालिया घोषित करने के बजाय केवल अटकती परियोजनाओं के समाधान पर ध्यान दिया जाए। समिति का मानना है कि इस क्षेत्र में खरीदारों की प्राथमिकता पैसा वापस पाने के बजाय अपने घर का निर्माण पूरा होना और कब्जा प्राप्त करना होती है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित इस समिति में कॉर्पोरेट मामलों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने 55 प्रमुख मुद्दों की समीक्षा कर 155 सिफारिशें की हैं। इसमें आईबीसी और ररा के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हों और खरीदारों का भरोसा मजबूत हो सके।

गोदरेज प्रॉपर्टीज की बिक्री बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर

कंपनी की बिक्री 16 प्रतिशत बढ़ी, 34,171 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार



नई दिल्ली।

रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत आवासीय मांग के दम पर अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी की बिक्री बुकिंग सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 34,171 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इस दौरान उसने 32,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। इस अवधि में कुल 17,515 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई, जिनका संयुक्त क्षेत्रफल लगभग 2.7 करोड़ वर्ग फुट रहा। मात्रा के आधार पर बिक्री में भी सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी का यह अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बुकिंग मूल्य और वॉल्यूम बताया जा रहा है। कंपनी के एक वे रिज अे धिकारी के अनुसार यह प्रदर्शन भारत के प्रमुख महानगरों में मजबूत आवासीय मांग को दर्शाता है। कंपनी का फोकस भविष्य में भी परियोजनाओं के विस्तार और निवेश पर रहेगा।

रुपया 10 पैसे की बढ़त के साथ 92.41 प्रति डॉलर रह

रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 92.51 पर बंद हुआ था

मुंबई।

रुपया शुक्रवार को 10 पैसे मजबूत होकर 92.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये में कारोबार के दौरान भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्योंकि बैंकों को अपने ओवरनाइट पोजिशन को 10 करोड़ डॉलर तक सीमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के निर्देशों की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.58 पर खुला। फिर शुक्रवाती कारोबार में 92.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया गुरुवार को तीन पैसे की मामूली बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.51 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.69 पर रहा।



ब्रोकोली में पाए जाते हैं औषधीय गुण

आप जानते हैं ब्रोकोली एक प्रमुख सब्जी है, जो की गोभीय वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत आती है। ब्रोकोली दिखने में फूलगोभी की तरह ही दिखाई देती है लेकिन इसमें पोष्टिकता फूलगोभी से ज्यादा होती है। यह एक पोष्टिक इटालियन गोभी है। जिसे मूलतः सलाद, सूप, व सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रोकोली को हरी गोभी भी कहा जाता है ब्रोकोली में गोभी से अधिक भाव और अधिक फूल प्राप्त होते हैं गोभी के पौधे पर एक ही फूल प्राप्त होता है लेकिन ब्रोकोली के एक ही पौधे से 4 से 5 फूल प्राप्त होते हैं। भारत में इसकी खेती ज्यादातर उत्तर भारत में की जाती है।

ब्रोकोली में पाए जाने वाले औषधीय गुण

ब्रोकोली हरी सब्जी के रूप में लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो सब्जी को पोष्टिक बनाता है। इसके अलावा इसमें फाइटोकेमिकल्स और एंटी-ऑक्सीडेंट भी होता है, जो बीमारी और बॉडी इम्फेक्शन से लड़ने में सहायक होता है। ब्रोकोली विटामिन सी से भरपूर है। यह कई बीमारियों से बचाने के साथ ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के भी खतरे को कम करती है।

बुवाई का समय

ब्रोकोली की खेती के लिए नर्सरी तैयार करने का समय अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा होता है, परतीय क्षेत्रों में कम उंचाई वाले क्षेत्रों में सितम्बर-अक्टूबर, मध्यम उंचाई वाले क्षेत्रों में अगस्त, सितम्बर, और अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में मार्च-अप्रैल में तैयार की जाती है।

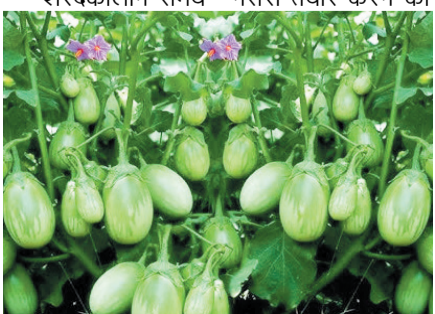
दूरी

बाकी फसलों से ज्यादा सख्त होती है बैंगन की फसल

भारत में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को उगाया है, जिनमें एक बैंगन है। बैंगन भारत में ही पैदा हुआ और आज आलू के बाद दूसरी सबसे अधिक खपत वाली सब्जी है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक बैंगन उगाने वाला देश है। यह देश में 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाया जाता है। हमारे देश के अलावा भी यह अन्य कई देशों की प्रमुख सब्जी की फसल है। बैंगन में विटामिन ए तथा बी के अलावा कैल्शियम, फॉस्फोरस और लोहे जैसे खनिज भी होते हैं। बैंगन की खेती पुरे वर्ष की जा सकती है, बैंगन की फसल बाकी फसलों से ज्यादा सख्त होती है। इसके सख्त होने के कारण इसे शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। भारत देश में बैंगन उगाने वाले मुख्य राज्य मध्यप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हैं।

बुवाई का समय

बैंगन की खेती के लिए बैंगन की बुवाई पुरे वर्ष भर में किसी भी समय की जा सकती है। वर्षाकालीन समय- नर्सरी तैयार करने का समय फरवरी से मार्च और मुख्य खेत में रोपाई का समय मार्च से अप्रैल उचित है।



15 सेमी. ऊंची हुई हो।

बीज की मात्रा

ब्रोकोली की नर्सरी में बुवाई के लिए 400-500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर (8-10 ग्राम प्रति नाली) पर्याप्त होता है।

बीज उपचार

ब्रोकोली की पौध तैयार करने के दौरान बीज को उपचारित कर नर्सरी में लगाना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए थीरम या कैप्टन दवा की उचित मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए।

खाद एवं रासायनिक उर्वरक

उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना उपयुक्त रहता है 7 अच्छी उपज के लिए खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 15-20 टन गोबर / कम्पोस्ट खाद, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग किया जाना अनुकूल होता है।

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवार की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर निराई-गुड़ाई करना चाहिए।

बीज को पंक्तियों में 4-5 से.मी. की दूरी पर बोना चाहिए। गहराई बीजों की 2.5 से.मी. की गहराई पर बुवाई करना चाहिए।

बुवाई का तरीका

ब्रोकोली की बुवाई बीजों द्वारा नर्सरी में इसकी पौध प्रो-ट्रे और क्यारियों में तैयार की जाती है, और उसके बाद खेत में रोपण किया जाता है। नर्सरी की तैयारी में इस बात का ध्यान रखें की नर्सरी जमीन से

समय जून से जुलाई और मुख्य खेत में रोपाई का समय जुलाई से अगस्त उचित है। बसंतकालीन समय- नर्सरी तैयार करने का समय दिसम्बर और मुख्य खेत में रोपाई का समय दिसम्बर से जनवरी उचित है।

दूरी

लाईन से लाईन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और लाईन में पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें।

गहराई

नर्सरी में बीज की बुवाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें।

बुवाई का तरीका

बैंगन की खेती के लिए पौधरोपण हेतु बीजों द्वारा नर्सरी तैयार की जाती है।

नर्सरी तैयार करने का तरीका

एक हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिये एक मीटर चौड़ी और तीन मीटर लम्बी करीब 15 से 20 क्यारियों की आवश्यकता होती है। बीज की 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर, 3 से 5 सेंटीमीटर के अन्तर पर कतारों में बुवाई करें और बुवाई के बाद गोबर की बारीक खाद की एक सेंटीमीटर मोटी परत से ढक दें तथा फव्वारों से सिंचाई करें।

बीज की मात्रा

एक हेक्टेयर में पौध रोपाई के लिये 500-750 ग्राम बीज और हाइब्रिड बीज की मात्रा 250 ग्राम/हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।

बीज का उपचार

नर्सरी में बीज बुवाई से पहले बीजों को थीरम 3 ग्राम या कार्बेनडाजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज से

सिंचाई

ब्रोकोली के पौधों को पानी की सामान्य जरूरत होती है। लेकिन पौध को खेत में लगाने के तुरंत बाद उनकी सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद इसके पौधों को आवश्यकता के आधार पर 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। इसके पौधे को पककर तैयार होने के लिए लगभग 5 से 6 सिंचाई की ही जरूरत होती है।

फसल की कटाई

ब्रोकोली की फसल की कटाई के लिए पौधरोपण के 65-70 दिन बाद तैयार हो जाते हैं, ब्रोकोली का फूल जब गठा हुआ, हरा व उचित आकार का हो तभी डटल सहित तोड़ना चाहिये। तुड़ाई करने में विलम्ब होने से शीर्ष (फूल) में पीलापन तथा स्वाद में विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भंडारण

ब्रोकोली को तुड़ाई के बाद बाजार में बिकने तक उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है। अन्यथा ब्रोकोली खराब होने लगती है। इसके लिये या तो ब्रोकोली को बर्फ के साथ पैकिंग करें या ठंडे कमरे में रखें अथवा ठंडे पानी का छिड़काव करें। उचित रखरखाव करें इसमें ब्रोकोली खराब नहीं होगी तथा बाजार पहुंचने तक ताजी एवं गुणकारी रहेगी।

उत्पादन

ब्रोकोली की उन्नत तरीके से खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ब्रोकोली की साधारण किस्मों से 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्मों से 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है।



उपचार करें।

खाद एवं रासायनिक उर्वरक

बैंगन की खेती में मिट्टी की जांच के अनुसार खाद और उर्वरक जालनी चाहिए। अगर मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है तो खेत तैयार करने समय 20-30 टन/हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद प्रति हेक्टेयर में 200 किलो ग्राम यूरिया, 370 किलो ग्राम सुपर फॉस्फेट और 100 किलो ग्राम पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवार की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर निराई-गुड़ाई करना चाहिए।

सिंचाई

बैंगन के पौधों की अच्छी बढ़वार लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए। गर्मी के मौसम में हर 3-4 दिन बाद पानी देना चाहिए और सर्दियों में 12 से 15 के अंतराल में पानी देना चाहिए। कोहरे वाले दिनों में फसल को बचाने के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें और लगातार पानी लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बैंगन की फसल में पानी खड़ा न हो, क्योंकि बैंगन की फसल खड़े पानी को सहन नहीं कर सकती है।

उत्तम सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें।

फसल की कटाई

खेत में बैंगन की पैदावार होने पर फलों की तुड़ाई पकने से पहले करनी चाहिए। तुड़ाई के समय रंग और आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैंगन का मंडी में अच्छा रेट मिले इसके लिए फल का चिकना और आकर्षक रंग का होना चाहिए।

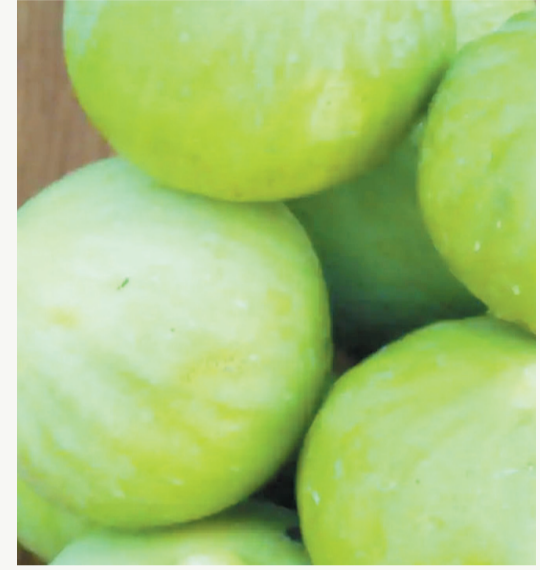
भंडारण

बैंगन को लंबे समय के लिए भंडारण नहीं किया जा सकता है। बैंगन को आम कमरे के सामान्य तापमान में भी ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से इसकी नमी खत्म हो जाती है। हालांकि बैंगन को 2 से 3 सप्ताह के लिए 10-11 डिग्री सेल्सियस तापमान और 92 प्रतिशत नमी में रखा जा सकता है। किसान भाई बैंगन को कटाई के बाद इसे सुपर, फेंसी और व्यापारिक आकार के हिसाब से छांट लें और पैकिंग के लिए, बोरियों या टोकरीयों का प्रयोग करें।

उत्पादन

बैंगन की खेती में उत्पादन मौसम, विविधता से विविधता और स्थान से स्थान तक भिन्न होती है। तथापि, सामान्य तौर पर बैंगन के स्वस्थ फलों की 250 से 500 क्विंटल/हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है।

बहुत ही गुणकारी है टिंडे



टिंडा कुकरबिटेसी कुल परिवार की यह सब्जी बहुत ही गुणकारी है। टिंडे को गोल तरबूज, गोल लौकी भी कहा जाता है 7 यह उत्तरी भारत की सबसे महत्वपूर्ण गर्मियों की सब्जी है। टिंडे का मूल स्थान भारत है। इसके कच्चे फल सब्जी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके फल की औषधीय विशेषताएं भी हैं, सूखी खांसी और रक्त संचार सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टिंडे की खेती उत्तरी भारत में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आन्ध्रप्रदेश में की जाती है।

बुवाई का समय

टिंडे की बुवाई का समय फरवरी-मार्च जायद के लिए और खरीफ की फसल के लिए जून-जुलाई में भी बोया जा सकता है।

दूरी

बीजों को क्यारियों के दोनों तरफ बोये और 45 से.मी. दूरी का प्रयोग करें।

बीज की गहराई

बीजों को 2-3 से.मी. की गहराई में बोयें।

बुवाई का तरीका

बीजों को सीधे या समतल क्यारियों (मेड़) पर बोया जा सकता है।

बीज की मात्रा

टिंडे की एक हेक्टेयर फसल की बुवाई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।

बीज उपचार

रोग नियंत्रण के लिए बीजों को बोने से पूर्व बाविस्टीन या मैकोजेब 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए।

खाद एवं रासायनिक उर्वरक

खेत तैयारी के समय कार्बनिक खाद के रूप में गोबर की खाद 20-25 टन प्रति हेक्टेयर व 100 किलो ग्राम नाइट्रोजन, 50 किलो ग्राम फास्फोरस व 50 किलो ग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। सम्पूर्ण गोबर की खाद, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को अंतिम जुलाई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष 2/3 नाइट्रोजन की मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर टापड्रैसिंग के रूप में प्रथम बार बुवाई के 25 से 30 दिन बाद तथा 40 से 45 दिन पर फूल आने के समय देना चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवार की रोकथाम के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना चाहिए।

सिंचाई

ग्रीष्म कालीन फसल की प्रति सप्ताह सिंचाई करें वर्षा कालीन फसल की सिंचाई वर्षा पर निर्भर रहती है 7 फूल एवं फलन के समय खेत में उचित नमी जरूरी है। वर्षाकालीन मौसम में जल निकास की उचित व्यवस्था आवश्यक है।

फसल की कटाई

किस्म के आधार पर बुवाई के 60 दिनों में फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फल पक जाए और मध्यम आकार के हो जायें तब तुड़ाई कर लें। 4-5 दिनों के फासले पर तुड़ाई करें।

उत्पादन

टिंडे की फसल का उत्पादन बीजों की गुणवत्ता, बुवाई का समय, भूमि की किस्म, जलवायु व ताप आदि पर निर्भर होता है, टिंडे की फसल से अनुकूल परिस्थितियों में फसल से प्रति हेक्टेयर 80 से 120 क्विंटल पैदावार मिल जाती है।

भंडारण

फल की तुड़ाई के बाद आवश्यकतानुसार फलों को किसी छायादार स्थान पर 2 से 3 दिन तक किसी टोकरी में रखकर भंडारित कर सकते हैं। इस दौरान फलों पर बीच-बीच में पानी का छिड़काव करना जरूरी होता है।



संक्षिप्त समाचार

नाइजीरिया के दो गांवों पर बंदूकधारियों ने किया हमला, कम से कम 20 लोगों की मौत

अबुजा, एजेंसी। नाइजीरिया के उत्तर-मध्य क्षेत्र में बंदूकधारियों ने दो गांवों पर हमला कर कम से कम 20 लोगों की हत्या कर दी। स्थानीय निवासियों ने यह जानकारी दी है। हमले मंगलवार तड़के नाइजर राज्य के शिरोरो क्षेत्र में स्थित बगना और एरेना गांवों में हुए। शिरोरो, राजधानी अबुजा से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। एरेना के निवासी जिब्रिन इसाह ने बताया, 'हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। यह तड़के का समय था, इसलिए हमला पूरी तरह से अचानक हुआ।' स्थानीय लोगों के अनुसार, हमले में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई लोग अब भी लापता हैं। हालांकि, पुलिस ने केवल तीन लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर कई घंटों तक गांवों में सक्रिय रहे, घरों में लूटपाट की और लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी इलाकों में भागने पर मजबूर कर दिया।

शोख हसीना के 'सियासी अंत' पर मुहर?: आवामी लीग आतंकी संगठन घोषित, बांग्लादेश संसद ने लगाया स्थायी बैन

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की संसद ने बेहद सख्त कानून पारित किया है। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री शोख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को आधिकारिक कानूनी मोहर लगा दी गई है। अब आवामी लीग बांग्लादेश में एक प्रतिबंधित संगठन है। संसद में गृह मंत्री सलाहद्दीन अहमद ने इस विधेयक को पेश किया। हालांकि उन्होंने सही तौर पर आवामी लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह कानून एक ऐसी संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए है जो 'नरसंहार और आतंकी गतिविधियों' में शामिल रही है। यह नया कानून पिछले 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम' में संशोधन है, जिसे पहले मुहम्मद युनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। इस कानून के लागू होने के बाद अब आवामी लीग का चुनाव आयोग में पंजीकरण स्थायी रूप से रद्द रहेगा। पार्टी न तो चुनाव लड़ सकेगी और न ही किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि कर पाएगी। कानून में यह भी प्रावधान है कि सोशल मीडिया या मूख्यधारा की मीडिया में पार्टी के समर्थन में कोई भी बयान प्रकाशित करना अपराध माना जाएगा। यहां तक कि पार्टी के समर्थन में जुरूस निकालना या भाषण देना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस विधेयक का विरोध केवल बाहर से नहीं, बल्कि संसद के भीतर से भी हुआ है। मुख्य विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शाफीकुर रहमान ने बिल की समीक्षा के लिए और समय मांगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मानवाधिकार अधिकारियों ने इस कदम की आलोचना की है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के स्वस्थ भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सर्वैधानिक विशेषज्ञ स्वाधीन मलिक ने कहा कि दुनिया के इतिहास में बांग्लादेश दूसरा ऐसा देश बन गया है, जिसने अपनी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी को ही बैन कर दिया है।

ट्रंप को पसंद नहीं आया 10 शर्तों वाला पीएस प्लान, टूट जाएगा सीजफायर?

वाशिंगटन, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुआ दो हफ्तों का युद्धविराम अब अनिश्चितता के दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। लेबनान पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों के कारण तनाव बढ़ गया है। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि यदि ये हमले नहीं रुके तो वह सीजफायर से पीछे हट सकता है। इसी बीच, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ईरान के कथित 10 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया था और इसे 'कूड़ेदान में फेंक दिया गया।' 'ईरान ने पहले दावा किया था कि उसका 10-पॉइंट प्रस्ताव अमेरिका को स्वीकार्य था, लेकिन लेविट ने इसे गलत बताया। उनका अनुसार, यह प्रस्ताव 'गेर-गंभीर' था और अमेरिकी नेतृत्व ने इसे बातचीत के लायक नहीं माना। हालांकि, बाद में ईरान की ओर से एक संशोधित योजना पेश की गई, जिसे अमेरिका ने अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के साथ जोड़कर बातचीत के आधार के रूप में देखने की बात कही है। लेविट ने यह भी दोहराया कि ट्रंप प्रशासन की 'रेड लाइन' साफ है ईरान के भीतर यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान की 'विश लिस्ट' को किसी समझौते के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव में कई बड़ी मांगें शामिल थीं, जैसे उस पर किसी भी तरह का हमला न होना, होमुज जलडमरूमध्य पर उसका नियंत्रण बनाए रखना, यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की अनुमति, सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंधों को हटाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को समाप्त करना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्तावों को खत्म करना, मुआवजा और क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। इसके अलावा, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की भी मांग की गई थी।

पाकिस्तान की बड़ी फजीहत; ट्रंप की टीम ने देखा था शहबाज का ट्वीट, फिर दी पोस्ट करने की इजाजत

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका-ईरान संघर्ष में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की पूरी कहानी एक सोशल मीडिया गलती के कारण खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर युद्धविराम की अपील वाला पोस्ट डाला था, लेकिन उसमें झूफट पाकिस्तान पीएम मैसेज आन एक्स लिखा हुआ छूट गया। बाद में इसे एडिट कर हटा दिया गया, लेकिन स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। कहा जा रहा है कि पाक पीएम ने ये पोस्ट अमेरिका के कहने पर पोस्ट की थी। अब खुद अमेरिकी मीडिया भी इस पर मुहर लगाती नजर आ रही है।

व्हाइट हाउस ने देखा था ट्वीट : न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने इस पोस्ट को एक्स पर शेयर किए जाने से पहले ही देख लिया था और अपनी मंजूरी भी दे दी थी। यह खुलासा दर्शाता है कि पाकिस्तान की स्वतंत्र कूटनीतिक पहल असल में अमेरिका की तैयारी की गई स्क्रिप्ट थी। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट ऑफ होमुज को दोबारा खोलो, वरना अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे और सभ्यता को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने 7 अप्रैल (मंगलवार) को शाम 8 बजे (वाशिंगटन समय) तक की डेडलाइन दी थी। इसी बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने



पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त संपर्क साधे हुए थे। फाइनल शर्तों टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को इस अस्थायी युद्धविराम को फाइनल करने के लिए दबाव डाला था, ताकि ट्रंप सार्वजनिक रूप से धमकियां देते हुए भी पीछे हट सकें।

इसके बाद 8 अप्रैल को सुबह शहबाज शरीफ ने अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का सीजफायर हो गया है। पोस्ट में ट्रंप, जेडी वेंस, ईरानी नेताओं और अन्य को टैग किया गया था। लेकिन असली पोस्ट के ऊपर 'झूफट पाकिस्तान पीएम मैसेज आन

एक्स' लिखा हुआ था, जो एडिट हिस्ट्री में साफ दिखाई दिया। शरीफ के स्टॉफ ने इसे कॉपी-पेस्ट कर दिया और हटाना भूल गए। पाकिस्तानी अधिकारियों को इस अस्थायी युद्धविराम को फाइनल करने के लिए दबाव डाला था, ताकि ट्रंप सार्वजनिक रूप से धमकियां देते हुए भी पीछे हट सकें।

पर्दे के पीछे की कहानी : न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि व्हाइट हाउस ने इस स्ट्रेटमेंट को पहले ही देख लिया था और मंजूरी दे दी थी। यानी पाकिस्तान की अपील असल में पहले से कोऑर्डिनेट थी। ट्रंप ने ट्यू सोशल पर लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ईरान पर बमबारी दो हफ्तों के लिए रोकने का फैसला किया है। कुछ घंटों बाद शहबाज शरीफ ने दूसरा पोस्ट डालकर युद्धविराम की घोषणा का स्वागत किया।

पोस्ट के झूफट वाले स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। कई यूजर्स ने मजाक उड़ाया। लोग इसे कॉपी-पेस्ट पीएम, व्हाइट हाउस ने स्क्रिप्ट लिखी आदि कह रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार रयान ग्रिम ने लिखा- शरीफ ने जो भेजा गया था, उसे कॉपी-पेस्ट कर दिया, जिसमें 'झूफट पाकिस्तान पीएम मैसेज आन एक्स' भी शामिल था। उनके अपने स्टॉफ तो उन्हें ऐसे नहीं बुलाते।

पूर्व पीएम केपी ओली के बाद देउबा पर भी बालेन सरकार ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वारंट जारी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने से सियासी माहौल गरमा गया है। इससे पहले केपी शर्मा ओली पर भी कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे साफ है कि नई सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त दिखा रही है। इस पूरे मामले में काठमांडू जिला अदालत ने जांच एजेंसी की मांग पर यह वारंट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला जज महेंद्र खड्का की पीठ की मंजूरी के बाद लिया गया। जांच एजेंसी लंबे समय से देउबा, उनकी पत्नी और अन्य नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के दौरान कई नेताओं के घरों से जली हुई नकदी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। इनमें देउबा के घर से जुड़े दृश्य भी थे। फॉरेंसिक जांच में इन नोटों के असली होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया और व्यापक जांच

शुरू की गई। जानकारी के अनुसार, देउबा और उनकी पत्नी इस समय नेपाल में नहीं हैं। दोनों 26 फरवरी को इलाज के लिए उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने से, जिससे जांच एजेंसियों की कार्रवाई और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी वारंट जारी करने का मकसद इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इससे विदेश में मौजूद आरोपियों को हिरासत में लेकर नेपाल लाया जा सकता है। पांच मार्च को हुए चुनाव के बाद नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई शुरू हुई है। यह नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तार्की ने कहा कि वार्ता उपयोगी रही लेकिन इसमें कोई सफलता किसी के हथ नहीं लगी है। एजेंसी

'पूर्ण समझौते तक अमेरिकी सेना ईरान में रहेगी', ट्रंप का अल्टीमेटम; लेबनान पर फिर बरसे बम

वाशिंगटन, एजेंसी। ट्रंप ने कहा इसमें अमेरिकी जहाज, विमान और सैनिक शामिल होंगे, साथ ही अतिरिक्त गोला-बारूद, हथियार और वह सब कुछ जो दुश्मन के कमजोर किए गए ढांचे को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जरूरी हो। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि समझौते का पालन किसी भी कारण से नहीं हुआ, तो कार्रवाई बड़ी, मजबूत और ऐसी होगी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। ट्रंप ने आगे कहा यह लंबे समय पहले तय हुआ था और सभी झूठी बातें और बयानबाजी के बावजूद कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और होमुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सुरक्षित और खुला रहेगा।

लेबनान से दोगे गए रॉकेट को इस्त्राइल ने क्विथाने : इस्त्राएली सेना ने जानकारी दी है कि लेबनान की ओर से उत्तरी इस्त्राएल की दिशा में दोगे गए एक रॉकेट को सफलतापूर्वक हवा में ही रोक दिया



गया। इस हमले के बाद गलील क्षेत्र में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज उठे, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इस्त्राइल ने हाल ही में लेबनान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं।

इस्त्राइल ने फिर दक्षिण लेबनान पर बरसाए बम : इस्त्राएली सेना ने एक बार फिर बरूट

ईरान का बड़ा फैसला, जहाजों के लिए नए रास्ते तय ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना ने होमुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नए वैकल्पिक रास्तों का एलान किया है। यह कदम समुद्र में संभावित बारूदी सुरांगों (माइंस) से जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए उठया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, आईआरजीसी नौसेना ने सभी जहाजों को निर्देश दिया है कि वे इन तय मार्गों का पालन करें और उनकी निगरानी में ही गुजरें। नेनसाह बोले-ईरान कमजोर, इस्त्राइल मजबूत; जीत अब तक की शानदार इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतयाहू ने ट्वीट कर कहा कि इस्त्राइल ने अब तक की लड़ाई में शानदार जीत हासिल की है, जो पहले असंभव लगती थी। उनका कहना है कि अब ईरान पहले से कमजोर और इस्त्राइल पहले से मजबूत है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम वार्ता बेनतीजा, चीन की कोशिश हुई बेकार

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जारी जंगी हालात पर चीन में हुई वार्ता के दौरान पाकिस्तानी हुक्मरान स्थायी युद्धविराम तक नहीं पहुंच पाए हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वार्ता बिना ठोस नतीजे के खत्म हो गई। डॉन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बैठक में अफगानिस्तान ने लगातार पाकिस्तान पर तालिबान के मुद्दे को लेकर आंखें दिखाईं और तालिबान के कुछ सवालनों ने पाकिस्तानी अफसरों को परेशानी बढ़ा दी। दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पाया।

चीनीसी पश्तो ने भी कहा है कि चीन में हुई बैठक में तालिबान ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए आतंकवाद की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए कहा। इसके अलावा तालिबान ने डूज़ड लाइन (सीमा रेखा) को मान्यता नहीं देने की बात भी कही। तालिबान ने यह भी कहा कि अस्थायी युद्धविराम के बावजूद पाकिस्तानी सेना उसके क्षेत्र में हमले कर रही है। यद्यपि अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तार्की ने कहा कि वार्ता उपयोगी रही लेकिन इसमें कोई सफलता किसी के हथ नहीं लगी है। एजेंसी

मुत्तार्की का सख्त रवैया : चीन के अफसरों के सामने ही अफगानिस्तान के प्रतिनिधि अमीर खान मुत्तार्की ने सख्त रवैया अपनाया और पाकिस्तान को इस छह दिनी बैठक में दोड़क कह दिया कि हमारी कोशिश जंग को खत्म करने की रहेगी, लेकिन यह सब पाकिस्तान पर निर्भर करेगा।

समझौते में छह देश शामिल : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समझौता करने में पाकिस्तान समेत छह देश शामिल हैं। इनमें चीन, तुर्किये, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। चीन इस शांति वार्ता का नेतृत्वकर्ता है। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक टोटीपी को अफगानिस्तान से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक बात नहीं बन सकती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टोटीपी को सफलतापूर्वक हवा में ही रोक दिया

फिर चलेंगी मिसाइलें, पाकिस्तान का कराया सीजफायर टूटने की कगार पर? ईरान ने दे दी धमकी



तेहरान, एजेंसी। परिचम एशिया में हुए सीजफायर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खबर है कि ईरान की तरफ से इजरायल को धमकी दी गई है। तेल अवीव को उड़ाने की धमकियां लेबनान में हुए हमले के जवाब में दी गई हैं। खास बात है कि मध्यस्थ पाकिस्तान ने कहा था कि सीजफायर और अरब देश शांति भी शामिल है। जबकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतयाहू ने सार्वजनिक रूप से इससे इनकार कर दिया है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से इजरायल को चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है, 'अगर कुछ घंटों में दक्षिण लेबनान में फायरिंग नहीं रुकी, तो एयर और मिसाइल युक्ति तेल अवीव में हमला करेंगी...'।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका, अपने सहयोगियों के साथ, लेबनान और अन्य सभी जगहों पर तुरंत युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। यह फैसला अभी इसी वक्त से प्रभावी है।' ट्रंप और जेडी वेंस दोनों ने मना कर दिया : अमेरिका के उप

अमेरिका में जाति विवाद गहराया: भारतीय और हिंदू समुदाय को निशाना बनाने का आरोप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कैलिफोर्निया की नागरिक अधिकार नियामक एजेंसी के खिलाफ नौवीं सर्किट अपील न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संगठन का आरोप है कि एजेंसी ने गलत तरीके से जाति को हिंदू धर्म से जोड़ते हुए भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों को निशाना बनाया है।

विभाग द्वारा सिस्को सिस्टम्स और उसके दो प्रबंधकों के खिलाफ दर्ज शिकायत से जुड़ा है। इस शिकायत में जाति के आधार पर भेदभाव के आरोप लगाए गए थे और यह कार्रवाई कैलिफोर्निया के फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग एक्ट के तहत की गई थी। एंड हाउसिंग एक्ट के तहत ही जाति के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव का मामला दर्ज किया है। एचएएफ का आरोप है कि सीआरडी ने अपनी कार्रवाई में जाति को हिंदू धर्म और भारतीय मूल के कर्मचारियों से जोड़ने की कोशिश की। संगठन के मुताबिक, एजेंसी की शिकायत में जाति शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया और यह धारणा बनाई गई कि भारतीय कर्मचारियों के बीच जाति-आधारित भेदभाव होता है, जिसे कंपनी को रोकना चाहिए था। एजेंसी की कार्रवाई नस्लवादी और तथ्यहीन धारणाओं पर आधारित है



संगठन ने यह भी कहा कि एजेंसी की प्रस्तुति भारतीय और हिंदुओं के बारे में नस्लवादी और तथ्यहीन धारणाओं पर आधारित है। एचएएफ ने सीआरडी के एक पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें भारत की जाति व्यवस्था को कठोर हिंदू सामाजिक और धार्मिक पदानुक्रम बताया गया था। हालांकि, बाद में विभाग ने इस विवादाित वाक्यांश को हटा दिया और मामले को अप्रस्पष्टिक बताया, लेकिन संगठन का कहना है कि इससे मूल समस्या खत्म नहीं होती। फाउंडेशन का कहना है कि हिंदू सामाजिक और धार्मिक पदानुक्रम जैसे शब्द हटाने के बावजूद सीआरडी अब भी कंपनी के भारतीय, दक्षिण एशियाई और हिंदू कर्मचारियों पर जाति से जुड़ी नीतियां लागू

करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले का अस्पर केवल एक केस तक सीमित नहीं एचएएफ की सीनियर लीगल डायरेक्टर निधि शाह ने चेतावनी दी कि इस मामले का अस्पर सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू अमेरिकी, भारतीय अमेरिकी और दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। शाह ने आरोप लगाया कि नागरिक अधिकार विभाग अपनी प्रगतिय शक्तियों का इस्तेमाल उन्हीं अल्पसंख्यक समूहों को अलग करने के लिए कर रहा है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर है। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया के लोग, नियोक्ता और कारोबारी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी जाति के आधार पर कार्रवाई करते हुए इसका दोष हिंदू धर्म पर डाल रही है और यह आशंका जताई कि भविष्य में और हिंदू संगठनों या व्यक्तियों को निशाना बनाया जा सकता है।

जवानों का जज्बा: -19 डिग्री पर बॉर्डर की सुरक्षा कर रही एसएसबी, बर्फ पिघलाकर पी रहे हैं पानी

पिथौरागढ़ ।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव गुंजी में अप्रैल महीने में भी कड़के की सर्दी और भारी बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जहां देश के मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली और लखनऊ में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं गुंजी में तापमान माइनस 15 से माइनस 19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इस असामान्य मौसम ने स्थानीय निवासियों और सीमा पर तैनात जवानों दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुंजी, जो कि धारचूला क्षेत्र में स्थित एक उच्च हिमालयी गांव है, वहां भारी बर्फबारी के कारण पानी के

प्राकृतिक स्रोत पूरी तरह जम गए हैं। पेयजल पाइपलाइन में भी पानी जम चुका है, जिससे जल आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बर्फ पिघलाकर पानी प्राप्त करना पड़ रहा है। यही नहीं, निर्माण कार्य जैसे सामान्य काम भी बर्फ पिघलाकर ही किए जा रहे हैं।

सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान भी इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अधिक ठंड और बर्फबारी के बावजूद जवान लगातार भारत-नेपाल सीमा पर गश्त कर रहे हैं। वे न केवल बर्फ पिघलाकर पानी पीने को मजबूर हैं, बल्कि जमा देने वाली ठंड में भी

पूरी मुसौंदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। एसएसबी की 11वीं वाहिनी के जवान अल्फा कंपनी के नेतृत्व में नियमित पैट्रोलिंग कर रहे हैं, जो उनके साहस और समर्पण को दर्शाता है।

स्थानीय निवासी के अनुसार, क्षेत्र में चल रही विभिन्न पेयजल योजनाएं जैसे कालापानी से गुंजी तक की 10 किलोमीटर लंबी योजना और अन्य लिफ्ट योजनाएं बंद पड़ी हैं। ऐसे में लोगों को काली नदी से पानी लाना पड़ रहा है या फिर बर्फ पिघलाकर काम चलावा पड़ रहा है। लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे पिथौरागढ़ जिले में अप्रैल महीने में भी जनवरी जैसी ठंड महसूस की जा रही है। लोग ठंड से बचने के



लिफ्ट गर्म कपड़ों और आग का सहारा ले रहे हैं। यह स्थिति न केवल मौसम के असामान्य बदलाव को दर्शाती है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और जवानों के संघर्ष को भी उजागर करती है।

अप्रैल में जनवरी जैसी सर्दी का अहसास पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण अप्रैल में भी जनवरी महीने की तरह शीतलहर चल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं। फिर ठंड आने से पूरे जिले में शीतलहर चल रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है।

पिथौरागढ़ जिले की समुद्र तल से ऊंचाई 5,338 फीट (1,645 मीटर) है। जिले में स्थित गुंजी की समुद्र तल से ऊंचाई पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से ठीक दोगुनी यानी 10,000 फीट (3,200 मीटर) है।

आतंकी दाग से बेदाग हुए कर्नल पुरोहित बनेंगे ब्रिगेडियर, सेना ने लगाई प्रमोशन पर मुहर

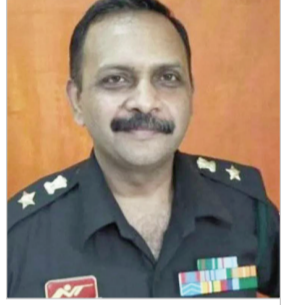
नई दिल्ली ।

भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक और भावुक फैसले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर रैंक पर पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है।

यह फैसला कर्नल पुरोहित के लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के करीब दो दशक कानूनी लड़ाइयों और जेल की सलाखों के पीछे बिताए हैं।

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद उनका चमकता हुआ सैन्य करियर पूरी तरह पटरी से उतर गया था। हालांकि, लंबी कानूनी जंग के बाद अब सेना ने उन्हें उनका हक देने का फैसला किया है।

कर्नल पुरोहित मूल रूप से 31 मार्च, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत ने तब करवट ली जब सशस्त्र बल



न्यायाधिकरण (एएफटी) ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिटायरमेंट पर रोक लगा दी।

ट्रिब्यूनल ने माना कि पुरोहित के साथ न्याय होना बाकी है। 31 जुलाई, 2025 को मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से ससम्मान बरी कर दिया था, जिसके बाद उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उनके खिलाफ सबूतों का अभाव है और अभियोजन पक्ष की कहानी विरोधाभासों से भरी थी।

यमुना नदी में स्टीमर पलटा, 10 पर्यटकों की मौत

नाव में 30 लोग थे सवार, 10 से ज्यादा लापता, राहत-बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ तैनात

सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख

मथुरा ।

उत्तर प्रदेश के वृंदावन में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया, जब यमुना नदी में 30 पर्यटकों से भरा एक स्टीमर पलट गया। इस दुर्घटना में 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिनमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सभी पर्यटक पंजाब के बताए जा रहे हैं, जो घूमने के लिए वृंदावन आए थे।

जिला प्रशासन के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट के पास हुआ, जो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे

के समय तेज हवा चल रही थी। एक पर्यटक ने मीडिया को बताया कि स्टीमर नदी के बीच में अचानक असंतुलित हो गया और तेज हवा के कारण उसकी रफ्तार बढ़ गई। इसी दौरान वह पीपा पुल से टकराकर पलट गया।

घटना के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। करीब 50 स्थानीय गोताखोर सर्च ऑपरेशन में जुटे। घायलों को रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम गाजियाबाद से मौके के लिए रवाना हो चुकी है, जबकि सेना से भी मदद मांगी गई है। फिलहाल लापता लोगों की तलाश जारी है



और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जब घटना हुई उस समय हवा की रफ्तार करीब 31 किमी प्रति घंटे थी।

इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बिना आधार के स्कूल में दाखिला नहीं? जानिए आरटीआई कानून का सच

नोएडा ।

सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिले के समय अक्सर आधार कार्ड को अनिवार्य बताया जाता है, इससे अभिभावकों में भ्रम पैदा होता है। लेकिन कानून और अदालत दोनों ने स्पष्ट किया है कि बिना आधार के भी बच्चों को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में शिक्षा का अधिकार, 2009 (आरटीआई) के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

यह अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। आरटीआई कानून के अनुसार, किसी भी बच्चे को दस्तावेजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने फैसले (पुडुस्वामी केस) में स्पष्ट किया कि स्कूल दाखिले के लिए आधार



कार्ड अनिवार्य नहीं है। यानी कोई भी स्कूल केवल आधार न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता।

उम्र प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल का रिकॉर्ड या अभिभावक का घोषणा पत्र स्वीकार किया जा सकता है। अगर ये भी नहीं हैं, तब भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता।

हाल ही में हरियाणा में लोक शिक्षण निदेशालय ने भी स्कूलर जारी कर बताया कि आधार या अन्य पहचान पत्र के बिना बच्चों

का दाखिला सुनिश्चित किया जाए। इसका विशेष जोर प्रवासी मजदूर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर है।

फिर भी, जमीनी स्तर पर कई स्कूल दस्तावेजों की मांग करते हैं और दाखिला देने से इनकार कर देते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार यह कानून की गलत व्याख्या और प्रशासनिक कमी के कारण होता है। यदि स्कूल दाखिला देने से मना करे, तब अभिभावक आरटीआई कानून की जानकारी देकर शिकायत कर सकते हैं।

श्रीहरिकोटा ।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के अपने सपने गगनयान की ओर एक और विशाल कदम बढ़ा दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो ने दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्राॅप टैंस्ट (आईएडीटी-02) को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह परीक्षण इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी सफलता ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा को पक्का कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस गौरवशाली उपलब्धि को देश के साथ साझा किया।

इस परीक्षण की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक डमी क्रू मॉड्यूल को कई किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया गया। मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा



तब होता है जब अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर ऊपर से वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं।

उस वक्त मॉड्यूल की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसे सुरक्षित उतारने के लिए पैराशूट का सही क्रम में खुलना अनिवार्य है। आईएडीटी-02 ने साबित कर दिया कि भारत का पैराशूट सिस्टम और रिक्वरी तकनीक पूरी तरह सटीक है। गगनयान मिशन के तहत तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों

को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती उन्हें सुरक्षित समुद्र में उतारना है।

इसरो की इस सफलता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि लैंडिंग के वक्त कोई अनहोनी नहीं होगी। यह मिशन अगले साल के लिए निर्धारित है और ऐसी हर कामयाबी भारत को उन गिने-चुने देशों की कतार में खड़ा कर रही है जो इसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखते हैं।

पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने वाले देश.....अब भारत के साथ मिलकर काम करने को बेताब

नई दिल्ली ।

भारत ने हाल ही में अपनी कूटनीति को सक्रिय करते हुए कई देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कड़ी में सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और तुर्की ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की कोशिश की है। नई दिल्ली में 8 अप्रैल को भारत और तुर्की के विदेश विभागों के बीच 12वें दौर की बैठक हुई, जिसमें भारत के वेस्ट सेक्रेटरी और तुर्की की डेप्युटी मिनिस्टर बैरिस इकनकी मौजूद रहें।

बैठक में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एनर्जी, एजुकेशन और कल्चर में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग ही नहीं, बल्कि बैठक में लोगों के बीच

कनेक्ट बढ़ाने और क्रॉस-बॉर्डर ट्रेडिज्म के खिलाफ मिलकर काम करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर आपसी दृष्टिकोण साझा किया। इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह सिर्फ बांग्लादेश या तुर्की तक सीमित नहीं है।

भारत ने हाल ही में अजरबाइजान के साथ भी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की दिशा में बातचीत की थी। छठे दौर की भारत-अजरबाइजान फॉरेंन ऑफिस कंसल्टेशन की बैठक काक में हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और क्रॉस-बॉर्डर ट्रेडिज्म के खिलाफ सहयोग के अवसरों पर चर्चा की।

यह रणनीति साफ तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की



स्थिति को मजबूत करती है। पहले जिन देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में कदम बढ़ाए थे, जैसे अजरबाइजान और तुर्की, अब वही देश भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने और गहरा करने की कोशिश में लगे हैं। इसी तरह बांग्लादेश का नया विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर हैं, जो दोनों देशों

के रिश्तों को नई मजबूती प्रदान करेगा। भारत की यह डिप्लोमेसी केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि ग्लोबल पैमाने पर भी प्रभाव डाल रही है।

पाकिस्तान के सहयोगियों की स्थिति में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। चीन के अलावा, जो पाकिस्तान के समर्थन में रहा है,

अब कई अन्य देश जैसे अजरबाइजान, तुर्की, और बांग्लादेश भारत के साथ आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग में बढ़ोतरी करने के लिए सक्रिय हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की रणनीति प्रभावित हो रही है और भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत हो रहे हैं।

प्रोत्साहन 2026 पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन



क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, भगवान महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा प्रोत्साहन 2026 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में कॉलेज

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 में आग, समय रहते पाया काबू

रत्नवे क्षेत्र से उठा धुआं तो कुछ उड़ानें अस्थायी रूप से रोकें



मुंबई ।

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर गुरुवार शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों मौके पर पहुंचीं और कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एयरपोर्ट प्रवक्ता के अनुसार, आग शाम करीब 6-10 बजे लगी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। आग ग्राउंड फ्लोर स्थित पावर हाउस के सीलिंग लेवल तक सीमित रही, लेकिन वहां मौजूद इलेक्ट्रिक ट्रे, वायरिंग, केबल, इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक पैनेल को नुकसान पहुंचा। सुरक्षा के महदेनजर एयरपोर्ट के सभी गेट कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए, जिससे यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। टर्मिनल-1 से संचालित कुछ उड़ानों को एहतियातन रोकना पड़ा, जिससे फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ। फिलहाल स्थिति सामान्य कर दी गई है और अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

चुनाव से पहले हुमायूं को बड़ा झटका, औवैसी की पार्टी ने तोड़ा गठबंधन

अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी एआइएमआइएम



कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। असदुद्दीन औवैसी की पार्टी एआइएमआइएम ने उनकी पार्टी 'आम जनता विकास पार्टी' के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब एआइएमआइएम राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि हुमायूं कबीर के हालिया बयान से मुस्लिम समाज की ईमानदारी और आत्मसम्मान पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में एआइएमआइएम किसी भी विवादित बयान से खुद को जोड़ना नहीं चाहती, इसलिए गठबंधन खत्म करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को इस्लामपुर में हुमायूं कबीर और औवैसी की संयुक्त रैली होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह गठबंधन टूट गया। इसके पीछे एक वायरल वीडियो को कारण बताया जा रहा है। इस वीडियो में हुमायूं कबीर किसी व्यक्ति से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ विवादित बातें सामने आई हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटना हुमायूं कबीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि एआइएमआइएम ने साफ कर दिया है कि वह अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी।

जांच के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा

प्रयागराज ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा। यह फैसला उस समय आया है जब उनके आवास पर कथित रूप से नकदी मिलने के मामले में आंतरिक जांच जारी थी। विवाद सामने आने के बाद उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को नई जिम्मेदारी की शपथ ली थी। फिलहाल आरोपों की इन-हाउस जांच प्रक्रिया चल रही थी और रिपोर्ट के आधार पर संसदीय कार्यवाई की संभावना जताई जा रही थी। इस्तीफे के बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि संभावित संसदीय प्रक्रिया का भविष्य क्या होगा और न्यायपालिका की जवाबदेही व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मामला कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

